



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 2005/पौष 7, 1927

No. 158]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28, 2005/PAUSA 7, 1927

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 26 दिसम्बर, 2005

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्र का उत्तरदायित्व) (संशोधन)
विनियम, 2005

फा. सं. आईआरडीए/विनि./4/2005/37.—बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 32ग को धारा 32ख के साथ पढ़ने पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमा सलाहकार समिति से सलाह लेते हुए प्राधिकरण, निम्नलिखित विनियमों बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्र का उत्तरदायित्व) (संशोधन) विनियम, 2002 को आगे संशोधित करता है, अर्थात् :—

- (1) इन विनियमों को बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्र का उत्तरदायित्व) (संशोधन) विनियम, 2005 के नाम से पुकारा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- (3) बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्र का उत्तरदायित्व) (संशोधन) विनियम, 2002 में,
 - (i) विनियम 3 के बाद, निम्नलिखित विनियम 3क जोड़ा जाएगा।

“3क—छठे वित्तीय वर्ष में उत्तरदायित्व :

प्रत्येक बीमाकर्ता, जो बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41), के लागू होने के बाद बीमा व्यवसाय प्रारंभ करता है, अधिनियम की धारा 32ख तथा 32ग के अन्तर्गत छठे वित्तीय वर्ष के प्रचालन के दौरान निम्नलिखित उत्तरदायित्वों के पालन के लिये वचनबद्ध होगा।

- (क) जीवन बीमाकर्ताओं के संबंध में, कुल प्रत्यक्ष रूप से लिखित पॉलिसियों का आट्टारह प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में होगा।
- (ख) गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के संबंध में, प्रत्यक्ष रूप से लिखित कुल सकल बीमा-किसत आय का पाँच प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में होगा, तथा
- (ग) सभी बीमाकर्ताओं के संबंध में, सामाजिक क्षेत्र में पच्चीस हजार नये जीवनों का आवरण होगा तथा पॉलिसी वर्ष के 31 मार्च को लागू रहनी चाहिये।”

सी. एस. राव, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/असाधारण/161/05]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**NOTIFICATION**

Hyderabad, the 26th December, 2005

**Insurance Regulatory and Development Authority (Obligation of Insurers to Rural or Social Sectors)
(Amendment) Regulations, 2005**

F. No. IRDA/Reg./4/2005/37.—In exercise of the powers conferred by Section 32C read with Section 32B of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Authority in consultation with the Insurance Advisory Committee hereby makes the following Regulations to further amend the Insurance Regulatory and Development Authority (Obligation of Insurers to Rural or Social Sectors) Regulations, 2002 namely:—

- (1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Obligation of Insurers to Rural or Social Sectors) (Amendment) Regulations, 2005.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) In the Insurance Regulatory and Development Authority (Obligation of Insurers to Rural or Social Sectors) Regulations, 2002,
 - (i) After Regulation 3, the following Regulation 3A shall be added.

“3A—Obligation in the Sixth Financial Year :

Every insurer, who begins to carry on insurance business after the commencement of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), shall, for the purposes of Sections 32B and 32C of the Act, ensure that he undertakes the following obligations, during the Sixth Financial year of operations :

- (a) In respect of life insurers, eighteen per cent of the total policies written direct shall be in the rural sector.
- (b) In respect of the non-life insurers, five per cent of the total gross premium income written direct shall be in the rural sector, and
- (c) In respect of all insurers, twenty five thousand new lives shall be covered in the social sector and the policies should be in force on 31st March of the year”.

C. S. RAO, Chairman

[ADVT. III/IV/Exty./161/05]